Leather Exports to have been of the order of—

Year	Value in Rs. million	Number of pairs in million
1984-85 . .	268	5.3
1985-86 . .	330	6.0
1986-87 . .	804	11.4

(c) There has been an increase in the export of leather footwear.

(d) An easy access to imported machinery, chemicals and accessories with concessional rate of duty, permission for export production of footwears in organised sector, training of personnel engaged in footwear production, design and product development, participation in overseas specialised commodity fairs, visit of sales/study delegations to different international markets, are some of the steps taken by Government to encourage the export of footwear.

प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में वक्तव्य

1099. **श्रीमती रेणुका चौधरी:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान श्री अनिल अग्रवाल, निदेशक विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र द्वारा इस आशय के कथन की ओर दिलाया गया है कि पिछले कुछ वर्षों से प्राकृतिक आपदायें बढ़ती चली जा रही हैं ;

(ख) क्या सरकार ने निदेशक महोदय के कथन का अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो अध्ययन के परिणामस्वरूप सरकार किस निष्कर्ष पर पहुंची है और इस संबंध में सरकार द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अंडं० आर० अन्तारी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

विज्ञान और पर्यावरण संबंधी केन्द्र के "द स्टेट आफ नेचर" (प्रकृति का प्रकोप) नामक प्रकाशन में प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख किया गया है :

1. 1960 के अन्त में देश का लगभग 25 मिलियन हैक्टर सूखा प्रवण क्षेत्र था यह बढ़ कर अब लगभग 65 मिलियन हो गया है ।

2. छठी योजना के आरम्भ में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) के अन्तर्गत 74 जिले थे इनकी संख्या अब बढ़ कर 100 जिले हो गई है ।

3. पिछले चार वर्षों के दौरान बाढ़ और सूखे से भारत के आधे से अधिक जिले प्रभावित हुए हैं ।

सरकार द्वारा की गई कार्रवाई :

1. सरकार का सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम 1973-74 में आरम्भ किया गया था और तब से यह निरन्तर सूखा प्रवण क्षेत्रों की समस्याओं से जूझ रहा है । रेगिस्तान के प्रभाव को नियंत्रित करने के उद्देश्य से निर्धारित रेतीले और अर्ध रेतीले क्षेत्रों में रेगिस्तान विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है ।

2. सरकार ने राष्ट्रीय भूमि उपयोग और परती भूमि विकास परिषद की स्थापना की है । राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति तैयार की गई है । एक राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड की स्थापना की जा चुकी है । बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य प्रतिवर्ष परती भूमि के 5 मिलियन हैक्टर पर ईंधन

और चारे की किस्मों को उगाकर परती भूमि का वनीकरण करना है।

3. नदी घाटी परियोजनाओं में भूमि संरक्षण और बाढ़ प्रवण नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में समेकित जल-विभाजन प्रबन्ध संबंधी चालू केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों को कार्यान्वित किया जा रहा है। भूमि का कटाव रोकने के लि रेगिस्तानी क्षेत्रों में संरक्षण और वनीकरण का एक विशेष कार्यक्रम आरम्भ किया गया है।

4. बाढ़ नियंत्रण के लिए विधिवत कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है। बाढ़ के संबंध में पूर्वानुमान और चेतावनी केन्द्रों के नेटवर्क की स्थापना से समय पर बाढ़ संबंधी चेतावनी देकर जन-जीवन की हानि को रोकने और सम्पत्ति को न्यूनतम क्षति होने देने के उद्देश्य से लोगों का वहां से हटाने में बड़ी सहायता मिली है। सातवीं योजना में 2.5 मिलियन हैक्टर पर बाढ़ सुरक्षा कार्य करने का प्रस्ताव है और इसके लिए 947.39 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।

Pollution of Yamuna near Delhi

1100. SHRI KALPNATH RAI: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether any programmes have been drawn up for the prevention of pollution of waters of Yamuna river near Delhi caused by the flow of sewage and industrial wastes from the "nullahs' of the city; and

(b) if so, the details of funds provided for the purpose and the progress made so far in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI Z. R. ANSARI): (a) Yes, Sir.

(b) The total outlay for the Union Territory of Delhi during the Seventh Five Year Plan for urban sanitation is Rs. 140 23 crores.

The progress made so far in this regard is shown below:

1. Out of the 17 major drains falling into the river Yamuna (i) 7 drains have been totally intercepted; (ii) Sullage from 3 drains has been substantially trapped at source; and (iii) Oxidation pond treatment has been provided for discharge from 3 drains.

2. Capacity of existing sewage treatment plants and pumping stations has been augmented.

3. Branch sewers for diversion of waste waters away from the Yamuna have been laid.

दिल्ली क्षेत्र में नीम के पेड़ों का लगाया जाना

1101. **श्री भंवर लाल पंवार:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वन-रोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत नीम के पेड़ों के वृक्षारोपण में वृद्धि करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं या करने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जेड० आर० अन्सारी:): पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने दिल्ली प्रदेश सहित सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सम्बोधित अपने परिपत्र में बनियन, ईमली, जामुन तथा बांस के अलावा नीम के पौधारोपण की सिफारिश की है।

राजस्थान में लगाए गए पेड़

1102. **श्री भंवर लाल पंवार:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1984-85, 1985-86 और 1986-87 के दौरान राजस्थान में कितने पेड़ लगाए गये;

(ख) इस राज्य में इस अवधि में लगाये गए पेड़ों में से कितने प्रतिशत पेड़ जीवित बचे हैं; और

(ग) राजस्थान में पेड़ों की उत्तर जीविता की प्रतिशतता को बढ़ाने के लिए